5.1. विश्लेषण -

शिक्षा व समाज एक-दूसरे के पूरक है तथा शिक्षा का यह उद्देश्य ही होता है कि वह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे। शिक्षा के संदर्भ में जॉन लॉक का यह मानना है कि 'जिस तरह पौधों का विकास कृषि द्वारा होता है उसी तरह मानव का शिक्षा द्वारा'। अतः शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम है। लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति की बात करें तो यह पहले की अपेक्षा अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और उपभोगी समाज की तरफ लोगों को उन्मुख कर रही है। ऐसी स्थिति में लोगों का सामाजिक विकास तो हुआ है मगर साथ ही साथ बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा आदि ने भी जन्म लिया है। तत्पश्चात् उच्च शैक्षणिक संस्थानों से यह अपेक्षा की जाने लगी कि वह समाज में ऐसे ज़िम्मेदार विद्यार्थियों को तैयार करें जो व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास में भी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार एक नई परिपाटी के रूप में अमेरिका और यूरोप के देशों में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व, आध्यात्मिक सामाजिक उत्तरदायित्व आदि अवधारणाओं का विकास होना प्रारंभ हुआ। अतः इस शोध कार्य में सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में जिन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है उनमें 'विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व' (USR) प्रमुख हैं।

'विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व' एक नई विधा है जिसकी शुरूआत **चिली विश्वविद्यालय** (2001) के शोधार्थियों द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप हुई। इस विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने विश्व पटल पर यह सुझाव प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र हैं और उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ शिक्षण, शोध, नवाचार, आदि तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनकी यह नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसे जिम्मेदार नागरिकों को तैयार करें जो व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास में भी अपना सहयोग दे सकें। इसके पीछे शोधार्थियों ने यह तर्क दिया कि यदि विश्वविद्यालय के कर्मचारी तथा विद्यार्थी व्यापक स्तर पर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगें तो क्षेत्रीय स्तर पर जो समस्याएँ होगी उसका सरलता पूर्वक निदान किया जा सकेगा। अतः यह वैश्विक स्तर पर 'विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व' के क्षेत्र में किया गया सराहनीय प्रयास रहा।

चूँकि अमेरिका और यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक स्थिति वैश्विक स्तर पर उच्च थी इसलिए इस विचारधारा (USR) को यहाँ प्रसारित होने में अधिक समय नहीं लगा। यहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में जो कार्य सरकार और कार्पोरेट सेक्टर मिलकर करते थे वह अब विश्वविद्यालयों द्वारा भी किए जाने लगे। इस प्रकार जब व्यापक स्तर पर इनके कार्यों की समीक्षा की गई तो सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने कार्य अन्य संस्थानों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली दिखे। तभी वैश्विक पटल पर यह प्रश्न उभरकर सामने आया कि आखिर क्या कारण है कि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तभी विद्वानों ने अपने अध्ययन में यह पाया कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों की सामाजिक समझ अन्य क्षेत्र के लोगों की तुलना में बेहतर है। इसके पीछे विद्वानों ने यह तर्क दिया कि सरकार और कार्पोरेट सेक्टर समाज का एक अभिन्न तो है लेकिन उनकी सामाजिक सहभागिता लोगों के बीच जितनी है उनसे कहीं अधिक शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों की है क्योंकि इन संस्थानों में कार्यरत लोग प्रत्यक्ष रूप से समाज से किसी-न-किसी तरह से जुड़े होते हैं। इस कारण ये लोग किसी समस्या का समाधान अन्य लोगों की अपेक्षा कुशलतापूर्वक निकालने में सक्षम होगें।

इस प्रकार व्यापक स्तर पर इन देशों की सरकार ने विश्वविद्यालय को यह सुझाव दिया कि वह चाहे तो अपने कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तत्पश्चात् यहाँ के विश्वविद्यालयों ने अपने कर्मियों और विद्यार्थियों को यह छूट दी कि वह चाहे तो कार्य समय (अध्ययन-अध्यापन) के दौरान ही 'सामाजिक उत्तरदायित्व' के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। इस विचारधारा का लोगों ने समर्थन किया और यहीं से विश्वविद्यालयी स्तर पर सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा दिया गया। इसी क्रम में यहाँ के विश्वविद्यालयों ने कर्मियों, विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रमों का सृजन इस तरह से किया कि विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही व्यावहारिक ज्ञान की समझ विकसित हो। सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में यहाँ के विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया यह सार्थक प्रयास था। अतः विश्वविद्यालयों द्वारा लिए गए इस तरह के निर्णयों से न सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर के लोगों में विकास हुआ

बल्कि समाज में रहने वाले उन सभी लोगों को इससे लाभ हुआ जो किसी-न-किसी तरह की समस्याओं से ग्रसित थे।

'विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व' की अवधारणा को अगर भारतीय पटल पर देखा जाए तो जो सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक स्थिति अमेरिका और यूरोप के देशों में है वह भारत की नहीं हैं। क्योंकि यहाँ की कार्य प्रणाली इन देशों की अपेक्षा बहुत ही जटिल है और अन्य देशों की तरह यहाँ कर्मियों को यह छूट नहीं है कि वह कार्यालयीय समय के दौरान किसी तरह की सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सके। इस कारण यहाँ के कर्मचारी एक निश्चित समय पर आते हैं और अपने कार्यों को ही प्राथमिकता देने में रह जाते है जिससे वे सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में किसी भी तरह की अपनी भूमिका नहीं अदा कर पाते हैं।

विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर इस अवधारणा को देखा जाए तो इनमें भी इसका अभाव है। क्योंकि भारत के विश्वविद्यालयों ने अध्ययन का पाठ्यक्रम इतना जटिल बनाया है कि विद्यार्थी अपना पूरा समय अध्ययन कार्य के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में नहीं दे पाते हैं। एक मुख्य बात यह भी है कि यहाँ के विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रम में इस तरह की गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं दिया है। इस प्रकार यहाँ बहुत कम ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देते हैं लेकिन बहुत कम ऐसे विभाग हैं जो अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण इस तरह से करते हैं कि विद्यार्थी सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकें, उदा. समाज कार्य, मानव विज्ञान। इसके लिए व्यापक पैमाने पर क्षेत्र आधारित पाठ्यक्रम, क्रियात्मक शोध, क्षेत्र आधारित परियोजनाओं का निर्माण आदि अवयवों को पाठ्यक्रम में शामिल किए हैं। इस कारण इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रत्येक छात्र किसी न किसी तरह से निश्चित तौर पर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता नजर आता है। इस तरह के कुछ अवयव अन्य पाठ्यक्रमों (जनसंचार विभाग, मानव विज्ञान विभाग, स्त्री अध्ययन विभाग) में भी शामिल किए गए हैं लेकिन यह अभी समाज कार्य विषय की तरह विकसित नहीं हो पाया है। यह प्रक्रिया सिर्फ विद्यार्थी केंद्रित ही नहीं है बल्कि शिक्षक केंद्रित भी है क्योंकि इस

पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षक भी किसी न किसी रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अपनी भूमिका को निभाते नज़र आते है। इसलिए भारत में अगर USR को बढ़ावा देना है तो सरकार एवं विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है-

- विश्वविद्यालय को अपने कर्मचारियों और विद्यार्थियों के अंदर इस बात की समझ विकसित करनी होगी कि उसका कार्य सिर्फ अध्ययन-अध्यापन तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसे समाज के हित में भी कार्य करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय को अपने कर्मचारियों और विद्यार्थियों को इस बात के लिए छूट प्रदान करनी होगी कि वह किसी नियत समय में भी सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कार्य कर सके।
- विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को क्षेत्र उन्मुख (Field Oriented) बनाना होगा ताकि छात्र सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ सके।
- विश्वविद्यालय को इस क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए उचित संसाधन मुहैया करना होगा।
- विश्वविद्यालयों को आज ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना होगा जो सामाजिक ज्ञान की शिक्षा दे और समाज में मौजूदा ज्ञान का दस्तावेजीकरण कर उसे ज्ञान परंपरा का हिस्सा बना सके।
- विश्वविद्यालयों को सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी पाठ्यक्रम भी बनाने होगें।
- विश्वविद्यालय को लक्षित समूह का निर्माण करना होगा।
- विश्वविद्यालय को पारंपरिक शिक्षण पद्धति की जगह नवीन शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना होगा।
- विश्वविद्यालय को अनौपचारिक परिसंवाद को बढ़ावा देना होगा।
- विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर सोचने के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर सोचना होगा।
- पाठ्यक्रम ऐसा हो जो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक विवेक का निर्माण करे।
- विश्वविद्यालय को सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियान्वयन हेतु स्वायत्त करना चाहिए।

- शैक्षणिक भ्रमण को पाठ्यक्रमों में शामिल करना होगा।
- विद्यार्थियों की सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय को एक विशेष दल (सेवा दल, सहायता दल आदि) का गठन करना चाहिए।
- विश्वविद्यालय को समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation-CBR) कार्यक्रमों द्वारा समाज के विकास पर बल देना होगा।
- विश्वविद्यालय को सामाजिक एवं प्रतिष्ठित नागरिकों से मिलकर समस्या समाधान हेतु कार्य करना होगा।
- विश्वविद्यालय को साप्ताहिक प्रेरक शिविर का आयोजन समय-समय पर करना होगा।
- विश्वविद्यालय को समय-समय पर व्याख्यान, नुक्कड़ नाटक, स्पोंसर शिप जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा।
- विश्वविद्यालय को सामुदायिक प्रयोगशाला (Community Lab) का निर्माण करना होगा।
- विश्वविद्यालय को हाशिएँ के समाज के लोगों से सीधे बातचीत करनी होगी।

उपर्युक्त सुझावों के आधार पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में 'विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व' की अवधारणा का विकास किया जा सकता है।

5.2. शोध प्रश्नों का विश्लेषण - इसमें कुल तीन प्रश्न समाहित थे जिसका विवरण निम्नलिखित है -

❖ **प्रथम प्रश्न का विश्लेषण -** 'विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व' की कार्य प्रणाली की समीक्षा अगर वैश्विक पटल पर किया जाए तो **अमेरिका** और **यूरोप** के देशों में इसके व्यापक क्षेत्र उभरकर सामने आए हैं जो निम्नलिखित है -

I. व्यावसायिक शिक्षा - यहाँ के अधिकांश विश्वविद्यालयों में आजकल व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों की यह ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की गई है वह शिक्षा के साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। यहाँ इस विचारधारा को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिला है और लगभग सभी संस्थान इस विधा का पालन करते है। अतः इसके अंतर्गत मुख्यतः तीन क्षेत्र निर्धारित किए गए है -

- सर्वप्रथम शिक्षा के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करना।
- समाज के हित के लिए कार्य करना।
- पर्यावरण का संरक्षण करना।

इस तरह यहाँ के उच्च शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है।

II. शोध - यहाँ के विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सामाजिक मुद्दों को आधार बनाकर शोध किया जा रहा है और क्रियात्मक शोध (Action Research) द्वारा समस्या का व्यावहारिक हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

III. सामाजिक जागरूकता - यहाँ के तमाम विश्वविद्यालयों ने अध्ययन का पाठ्यक्रम इस तरह का बनाया है कि छात्र पठन-पाठन के अतिरिक्त तमाम तरह के सामाजिक गतिविधियों (सामाजिक निति, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि) में भाग लेते हैं और लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं।

IV. सहयोग-आधारित परियोजना - यहाँ के विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय स्तर पर व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए स्वयं के स्तर से या अन्य संगठनों के सहयोग से परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है ताकि समस्या का उचित निदान किया जा सके।

V. अंतर-विश्वविद्यालय सहयोग - यहाँ के प्रत्येक विश्वविद्यालय समाज में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए एक दूसरे से सहयोग स्थापित करते है।

VI. विश्वविद्यालय-उच्च विद्यालय सहयोग - यहाँ के तमाम विश्वविद्यालय अपने से उच्च स्तर पर कार्य कर रही संस्थाओं का सहयोग लेते है और अपने ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा सामाजिक समस्याओं का हल निकलते हैं।

VII. अंतरराष्ट्रीय सहयोग - यहाँ के विश्वविद्यालय सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए यदि कोई संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही है तो उससे भी सहयोग लेते हैं।

VIII. उत्तरदायी परिसर - यहाँ के विश्वविद्यालय अपने परिसर के अंदर ऐसी अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करते हैं ताकि इसमें रहने वाला प्रत्येक सदस्य अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन उचित परिवेश में कर सके।

IX. सामुदायिक सहभागिता - इसके अंतर्गत यहाँ के तमाम विश्वविद्यालय सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं के स्तर से अथवा क्षेत्रीय स्तर पर जो संस्था कार्य कर रही है उससे जुड़कर सहभागिता को सफल बनाते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्य अमेरिका और यूरोप के देशों में 'विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व' के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करते हैं लेकिन वैश्विक पटल पर जैसे-जैसे इस अवधारणा का विकास हुआ इसमें और नए-नए आयाम जुड़ते गए।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि 'विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व' के कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम **'राधाकृष्णन आयोग'** (1947) ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के सामाजिक उत्तरदायित्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह दिशा-निर्देश जारी किया कि वे समाज के विविध मुद्दों से अवगत होकर उसके अनुरूप कार्य करे। यह सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में किया गया एक वैधानिक प्रयास था। चूँकि भारत लंबी अवधि से अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा इस कारण यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इस कार्य के प्रति अनुकूल नहीं रही और संस्थानों से जो अपेक्षा सरकार की थी वह पूरी न हो सकी। तत्पश्चात् सन् 1964 में **'भारतीय शिक्षा आयोग'** (कोठारी आयोग) का गठन 'दौलत सिंह कोठारी' की अध्यक्षता में किया गया। आयोग ने यह सुझाव दिया कि शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का एक शक्तिशाली साधन बनाया जाए जिससे राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। आयोग ने विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में समानता, सामाजिक न्याय, नवीन ज्ञान, सामाजिक तथा नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीय चेतना आदि को विकसित करना होगा। आयोग ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही और इनके लिए छात्रावास, अनुसंधान इकाई (Research Unit), छात्रवृत्ति और शिक्षाशास्त्र, गृह-विज्ञान, समाज कार्य (Social Work) जैसे पाठ्यक्रमों में इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कही। आयोग ने व्यापक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही और पॉलीटेक्निक, कृषि, इंजीनियरिंग आदि जैसे कॉलेज और विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने की बात कही। इस प्रकार आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में जो सुझाव प्रस्तुत किया है उसका पालन कर उच्च शैक्षणिक संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है।

सन् 1986 में **'राष्ट्रीय शिक्षा नीति'** बनी और शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार किया गया और नई शिक्षा नीति के तहत पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने आर बल दिया। इसमें स्त्री शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की शिक्षा, अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि के लिए विशेष उपबंध किया। इसमें खुले विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय (गांधी के विचारों पर आधारित), तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा आदि को बढ़ावा देने बात की गई। राष्ट्रीय शिक्षा

नीति ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार इस नई शिक्षा नीति ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के सामाजिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य का एक अलग रूप प्रस्तुत किया जो शैक्षणिक संस्थानों के सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रदर्शित करता है।

सन् 2005 में **पुणे विश्वविद्यालय** ने **'समर्थ भारत अभियान'** योजना को क्रियान्वित कर गाँव गोद लेने की परंपरा को आरंभ किया। यह सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा किया गया सराहनीय प्रयास था। आगे चलकर हरियाणा, दिल्ली, असोम क्षेत्रों के तथा इग्नू जैसे विश्वविद्यालयों और NAAC तथा UGC जैसी संस्थानों ने अपने स्तर से सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ कर दिया है। UGC ने 'बारहवीं पंचवर्षीय योजना' (2012-17) में एक दिशा-निर्देश जारी कर सामाजिक उत्तरदायित्व को सभी विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया। देश की वर्तमान सरकार (2014-19) ने सामाजिक हित का ध्यान रखते हुए **'उन्नत भारत अभियान'** कार्यक्रम को क्रियान्वयन कर उच्च शैक्षणिक संस्थानों के सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्धारित यह निर्देश दिया कि ये संस्थानों अपने स्तर से गाँवों का विकास करेंगे। यह भारतीय परिवेश में सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में किया जाने वाला सराहनीय प्रयास है।

भारत में सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में इन संस्थानों ने कार्य करने का एक प्रयास किया है लेकिन इसका विकास जिस तरह से पश्चिम के देशों में हुआ है यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक आदि परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं रही है। लेकिन सरकार और उच्च शैक्षणिक संस्थान इनकी सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास में है। यहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और विद्यार्थियों द्वारा जिन क्षेत्रों में कार्य किए जा उनमें स्वच्छता, जागरूकता, ग्राम शिविर, शिक्षा आदि महत्वपूर्ण हैं जिसका व्यापक विवरण निम्नलिखित है -

I. स्वच्छता - इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी ग्रामीण भ्रमण या कैंप के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहे हैं। वर्तमान सरकार ने भी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान रखते हुए **'स्वच्छ भारत अभियान'** (2014) कार्यक्रम को क्रियान्वित किए हुए है। इस विचारधारा को ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने **'उन्नत भारत अभियान'** के तहत IIT, NIT और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों को यह दिशा-निर्देश दिया है कि वह अपने स्तर से इसपर कार्य करे। तत्पश्चात् ये संस्थान अपने स्तर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों से जुड़कर व्यापक स्तर पर कार्य कर रहे है।

II. स्वास्थ्य - इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जगह-जगह कैंप लगाकर स्वास्थ्य के प्रति जो जन-जागरूकता फैला रहे हैं उनमें बीमारियों के प्रति लोगों को बताना, प्राथमिक उपचार की जानकारी देना, रक्त दान शिविर का आयोजन करना आदि महत्वपूर्ण है।

III. रोजगार - इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप स्थानीय रोजगार सृजित करने कार्य करने की तकनीक को बताते है साथ ही उद्यमिता विकास को प्रत्साहित करते हैं।

IV. जागरूकता - इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सरकारी नीति आदि से लोगों को अवगत कराते है।

V. देशज ज्ञान का दस्तावेजीकरण - इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय स्तर पर जो ज्ञान समाज में मौजूद है उसके दस्तावेजीकरण पर बल दे रही है ताकि इस तरह के ज्ञान का वैश्विक पटल पर प्रचार-प्रसार हो सके।

VI. शिक्षा के लिए पहल - इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय यह प्रयास कर रही है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। इसके लिए वह वह बड़े पैमाने पर सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्य भारतीय परिप्रेक्ष्य में 'विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व' के कार्य क्षेत्र को निर्धारित करते हैं लेकिन जब इसकी व्याख्या वैश्विक परिदृश्य में किया जाए तो इसके जो क्षेत्र उभरकर सामने आए है वह बहुत ही प्राथमिक स्तर के है। यहाँ सरकार एवं विश्वविद्यालयों को इसके बारे में एक बेहतर विकल्प की खोज करनी होगी, ताकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व की एक वृहद अवधारणा का निर्माण किया जा सके। इसके लिए विश्वविद्यालय को अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, कार्य पद्धति आदि में बदलाव लाने की आवश्यकता है।

❖ **द्वितीय प्रश्न का विश्लेषण -** इस प्रश्न की समीक्षा यदि भारतीय तथा वैश्विक पटल पर किया जाए तो यहाँ अनेक समस्याएँ देखने को मिली है -

I. शिक्षा का निम्न स्तर - भारत आदि काल से एक बहुआयामी और बहुसंस्कृति वाला रूढ़िवादी समाज रहा है। इस कारण यहाँ की शिक्षा व्यवस्था उस रूप में नहीं रही है जिस रूप में अमेरिका और यूरोप के देशों की है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 73 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) ही साक्षर है। यहाँ अधिकांशतः लोग ऐसे है जो संवैधानिक अधिकार, कर्तव्य आदि से अपरिचित है। इस स्थिति में सरकार द्वारा इनके लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है उससे वह या तो ये अपरिचित रह जाते है या कोई पढ़ा लिखा दूसरा वर्ग इसका लाभ उठा लेता है। ऐसी स्थिति में सरकार और संस्थानों के लिए भी यह चुनौती का विषय बना हुआ कि कैसे इनकी भागीदारी को सामाजिक क्षेत्र में बढ़ाया जाए। लेकिन यह स्थिति अमेरिका और यूरोप के देशों में नहीं है क्योंकि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तर की है।

II. भाषाई समस्या - भारत एक बहुभाषी देश है और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में किसी विशेष भाषा को ही मान्यता प्राप्त है। इसमें अध्ययन करने वाला छात्र और कर्मचारी भी विविध भाषाई प्रदेश से ताल्लुख रखते है। इस कारण जिस क्षेत्र में यह संस्थान रहते हैं वहाँ की भाषा या तो क्षेत्र होती है या अध्ययन करने वाला छात्र ही उस भाषा से अनभिज्ञ रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में जो कार्य निर्धारित किए रहते है वह सही रूप में सफलीभूत नहीं हो पाते है। लेकिन

इन देशों में इस तरह की भाषाई विविधता नहीं है इस कारण यहाँ के विश्वविद्यालयों ने सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अल्प समय में बेहतर कार्य कर रहे हैं।

III. राजनैतिक समस्या - जब कोई शोधकर्ता अथवा विद्यार्थी किसी सामाजिक समस्या को लेकर गाँव या शहर में अध्ययन के लिए जाते है तो यहाँ के राजनीतिक लोग कार्य प्रणाली में बाधा उत्तपन्न करते है। इससे इनकी मूल समस्याएँ या तो उजागर नहीं होती और यदि होती भी है तो वह सही नहीं होती। इस कारण संस्थानों के छात्र चाहकर भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते। लेकिन अमेरिका और यूरोप में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ की सरकार ने विश्वविद्यालयों को सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में कार्य करने हेतु छूट प्रदान की है।

IV. संसाधनों की कमी - भारत में विश्वविद्यालय और इसमें संबन्धित जुड़े लोगों को संसाधनों की समुचित व्यवस्था अमेरिका और यूरोप के देशों की तरह नहीं है। इस कारण यहाँ छात्र अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन सही रूप में नहीं कर पता है। लेकिन अमेरिका और यूरोप की सरकार इसके लिए व्यापक स्तर अपर संसाधन मुहैया करती है।

V. समन्वय की कमी - अमेरिका और यूरोप के देशों में सरकार का जनता से, जनता का सरकार से, सरकार का संस्थानों से और संस्थानों का जनता से जिस तरह से उचित समन्वय है उस तरह भारत में नहीं है। इस कारण यहाँ छात्र अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन सही रूप में नहीं कर पता है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों में सरकार और विश्वविद्यालयों का उचित समन्वय देखने को मिला है।

VI. आर्थिक समस्या - भारत में धनाभाव के कारण भी विश्वविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को इस पर कोई मजबूत कदम उठाना होगा। तभी सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना सही रूप में साकार हो पाएगी। लेकिन अमेरिका और यूरोप की सरकार अपने यहाँ के विश्वविद्यालयों के लिए अलग से धन मुहैया कराती है।

इस प्रकार भारतीय पटल पर सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन में अनेक समस्याएँ देखने को मिली है। इसके अलावा भी कई समस्याएँ हो सकती है।

❖ **तृतीय प्रश्न का विश्लेषण -** विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व एक व्यापक और विशद् अवधारणा है जिसमें अनेकों कार्य क्षेत्र, समस्याएँ एवं उनके समाधान की संभावनाएँ शोध कार्य के दौरान देखने को मिली हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएँ और कार्य क्षेत्र उभरकर सामने आए उनके स्वरूप अमेरिका और यूरोप के देशों से अलग थे। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो समाज कार्य हस्तक्षेप होगें उससे एक व्यापक दृष्टिकोण का निर्माण किया जा सकता है। अतः इसके अंतर्गत जो संभावित समाज कार्य हस्तक्षेप होंगे वह निम्नलिखित हैं -

- विश्वविद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को रचनात्मक (Innovative) बनाया जाए।
- शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान को विश्वविद्यालय से समाज की तरफ ही नहीं बल्कि समाज से विश्वविद्यालय की तरफ भी आना चाहिए।
- विश्वविद्यालय को समाज में हुए किसी तरह के बदलाव को पाठ्यक्रम में तत्काल शामिल किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालय को देशज ज्ञान के दस्तावेजीकरण पर बल देना चाहिए।
- विश्वविद्यालय में सहभागी शोध को बढ़ावा देना चाहिए।
- विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में क्षेत्र कार्य को प्राथमिकता देना होगा।

उपर्युक्त के अलावा भी अन्य समाज कार्य हस्तक्षेप हो सकते है। लेकिन इस और सरलीकृत करने के लिए अर्थात इसके और बेहतर कार्यान्वयन के लिए संभावित समाज कार्य हस्तक्षेप के तौर पर एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। इस मॉडल के तहत विश्वविद्यालय, सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।

भारतीय विश्वविद्यालयों हेतु विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रारूप

शैक्षणिक कर्मचारियों के सामाजिक उत्तरदायित्व

- शिक्षण
- शोध
- नवाचार
- प्रेरणा
- जागरूकता
- सौहार्दपूर्ण बातचीत
- सामुदायिक सहभागिता
- क्षेत्र-उन्मुख पाठ्यक्रम

गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के सामाजिक उत्तरदायित्व (उच्च-स्तर पर कार्यरत कर्मचारी)

- अच्छी योजना का निर्माण करना
- सकारात्मक परिवेश का निर्माण करना
- सामाजिक संवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना
- हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- सरकार से उचित समन्वय स्थापित करना

विद्यार्थियों के सामाजिक उत्तरदायित्व

- समाज में उचित समन्वय
- सामाजिक अध्ययन
- सामाजिक निदान
- सहभागी शोध
- सामाजिक सहभागिता
- सामाजिक सेवाएँ
- स्वैच्छिक सेवाएँ
- जागरूकता कार्यक्रम के लिए उचित समन्वय
- साक्षरता कार्यक्रम
- सामाजिक कार्य हेतु अहिंसात्मक दृष्टिकोण

I. प्राथमिक शिक्षा

II. ग्रामीण उद्योग

III. स्वास्थय और स्वास्थय शिक्षा

V. विकेंद्रीकरण

VI. जैविक खेती

IX. मद्यपान निषेध

- सतत् मूल्यांकन।

Model for University Social Responsibility in Indian Universities

Academic Staff Responsibility

- Teaching.
- Research.
- Innovation.
- Motivation.
- Awareness.
- Goodwill commitment.
- Community Engagement.
- To Create Field Oriented Curriculum.

Non-Academic Staff Responsibility in Higher level

- Make a Good Planning.
- To Provide a Good Environment.
- Motivated for Social Debate Competition in Campus.
- Ensure the Participation of Stack Holders.
- Proper Co-ordination with Government Body.

Student Social Responsibility

- Rapport Building to Society.
- Social study.
- Social Diagnosis.
- Participatory Research.
- Engagement with Society.
- Social Services.
- Voluntary Services.
- Co-ordination of Awareness Program.
- Literacy Program.
- Non-violence Approach to Social Work.

I. Basic Education.

II. Rural Industry.

III. Basic Education.

IV. Health and Health Education.

V. De-Centralization.

VI. Organic Farming.

IX. Prohibition of Alcohol.

- Continue Observation.

निष्कर्ष -

उपर्युक्त के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र हैं इसलिए इसे समाज के हित में कार्य करना चाहिए। लेकिन जब इसकी व्याख्या भारतीय और वैश्विक परिदृश्य में किया गया तो यह बात सामने निकलकर आई कि 'अमेरिका और यूरोप के देशों में विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व (USR) का विकास जिस रूप में हुआ उस रूप में भारत में नहीं हुआ है क्योंकि इन देशों की सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक स्थिति जिस तरह की है उस अनुरूप भारत में नहीं है। इसलिए भारत को अभी इस पर और बेहतर करने की आवश्यकता है। इस पर सुझाया गया मॉडल एक सहायक के रूप में कार्य करेगा जो किसी भी विश्वविद्यालय और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा'।